# भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

#### राज्य सभा

### अतारांकित प्रश्न सं. 1239

श्क्रवार, 16 अगस्त, 2013 को उत्तर देने के लिए

## एक हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी

- 1239. श्री राम जेठमलानी:
  - क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या देश में 204 परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं जिनमें प्रत्येक की निर्माण लागत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है;
- (ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और क्या इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब से बचने के लिये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा निगरानी की गयी है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ है और उनके निर्माण की लागत में मार्च, 2012 की तुलना में मार्च 2013 तक अधिक बढ़ोतरी पाई गई है ?

#### उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (श्री श्रीकांत क्मार जेना)

- (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, समय एवं लागतवृद्धि से संबंधित 150 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करता है । 31 मई, 2013 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा कुल 207 मेगा परियोजनाओं (1000 करोड़ रुपए एवं अधिक लागत वाली) की निगरानी की गई ।
- (ख) तथा (ग) अनुमितयों/अनुमोदनों से संबंधित मुद्दों सिहत 1000 करोड़ रुपए अथवा अधिक निवेश वाली पिरयोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए दिसंबर, 2012 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल सिमिति (सीसीआई) गठित की गई है ताकि उनका शीघ्र तथा समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कुल 183 मेगा पिरयोजनाओं की निगरानी की गई जिनमें से 86 पिरयोजनाओं के संबंध में विलंब की सूचना प्राप्त हुई । पिरयोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इन 183 पिरयोजनाओं के संबंध में 93,376.35 करोड़ रुपए की कुल लागतवृद्धि की सूचना दी गई ।
  - 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कुल 204 मेगा परियोजनाओं की निगरानी की गई जिनमें से 103 परियोजनाओं के संबंध में विलंब की सूचना प्राप्त हुई। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इन 204 परियोजनाओं के संबंध में 1,15,201.47 करोड़ रुपए की कुल लागतवृद्धि की सूचना दी गई।

\*\*\*